अब तक पता ही नहीं था

जाम और हादसों का कारण ढूंढने के लिये बनी कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट देगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सड़कों पर चलने वाले हर नागरिक को साफ़ नज़र व समझ आता है कि जाम क्यों लगते हैं और हादसें क्यों होते हैं ? लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये नवनियुक्त सीपी (पुलिस कमिश्नर) ने एसीपी ट्रैफ़िक के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। इसमें एक इन्जीनियर व एक अन्य व्यक्ति होगा। क्या पुलिस को वास्तव में ही नहीं पता कि जाम क्यों लगते हैं और हादसे क्यों होते हैं ? शहर से गुजरने वाले राजमार्ग पर औस्तन एक आदमी हर रोज़ अपनी जान कुर्बान कर रहा है और उसके बावजूद अभी तक पुलिस को इसके कारण ही नहीं पता तो यह हैरानी से कहीं अधिक शर्म की बात है।

सर्वविदित है कि इसके लिये सड़क निर्माण और पुलिस की ढिलाई दोनों ज़िम्मेवार हैं। शहर में शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जिस पर वाहनों व रेहड़ियों की अवैध पार्किंग न हो। अजरोंदा फ्लाई ओवर के दोनों ओर एक तो सड़क बनी ही संकरी है ऊपर से कोढ में खाज की तरह उसी पूरी सड़क पर वाहनों की अवैध पार्किंग लगी रहती है। इतना ही नहीं दुर्घटनाओं को निमंत्रण देती हुई एक खाई भी खुदी पड़ी है जिस पर बरसों से काम करने का नाटक हो रहा है। मामला केवल अजरोंदा मोड़ का ही नहीं लगभग सभी मोड़ों पर यही स्थिति है।

राजमार्ग के दोनों ओर सर्विस लेन नदारद है जबकि नक्शे में इसका प्रावधान है। पैदल सड़क पार करने वालों को लिये पुलों का प्रावधान है लेकिन ठेकेदार अनिल अम्बानी बना नहीं रहा, तमाम फ्लाई ओवरों पर रोशनी का प्रावधान है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लाडले अम्बानी को

कौन कहे। राजमार्ग पर चढने व उतरने की विधिवत कोई योजना सड़क बनाते वक्त नहीं रखी गयी, नेताओं द्वारा नारियल फ़ोड़ देने के बाद जब यह खामी नज़र आई तो बड़े बेढंगे तरीके से इसकी व्यवस्था की गयी। लोग पैदल सड़क पार न करें इसके लिये ग्रिल का प्रावधान तो है, परन्तु जब सैंकड़ों लोग सड़क पार करते हुये मारे गये और ज़्यादा हो हल्ला मचा तो ग्रिल लगाने की रस्म अदायगी शुरू की गयी। ग्रिल ऐसी लगाई जा रही है कि बच्चे भी उसे कूद कर पार कर लें और दो-चार झटकों में उसे तोड़ भी दें। ग्रिलों को टूटने से बचाने के लिये ठेकेदार ने बीच-बीच में गैप छोड़ दिये हैं ताकि ग्रिल फ़ांद कर या तोड़ कर निकलने की बजाय लोग वहां से गुजर सकें। तमाम फ्लाई ओवरों के नीचे से घूम कर वापस आने के लिये बनाये गये यू टर्न भी ग़ल्त हैं। इनको लाल बत्ती से और 20 मीटर पहले बनाना चाहिये था ताकि यू टर्न लेने वालों को लाल बत्ती तक जाना ही न पड़े।

किसी भी दुर्घटना होने पर पुलिस किसी न किसी वाहन चालक को दोषी ठहरा कर उसका चालान करके अपने कर्त्तव्य की इति श्री कर लेती है, कभी भी सड़क बनाने एवं उसकी देख-रेख करने वालों को दोषी नहीं बनाती। करीब 3 वर्ष पूर्व बाटा मोड़ पर सड़क पर गड्ढों के कारण हुई एक दुर्घटना में एक छोटे बच्चे की मृत्यु के मामले में भी जब पुलिस ने अपनी यही कवायद करते हुये एक वाहन को दोषी ठहरा कर चालान कर दिया तो बच्चे के पिता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को तलब कर के असल दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ़ कार्यवाही के आदेश तो दे दिये परन्तु अभी तक भी मामला लम्बित है।

यदि पुलिस सही ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सड़क निर्माण एवं उसकी देख-रेख से जुड़े लोग़ों के चालान करे तो दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लगता नही कि इससे अधिक जानकारी कोई जांच कमेटी सीपी साहब को दे पायेगी। अब देखना यह है कि इस जानकारी का उपयोग कैसे किया जाता है ?

हनुमान मंदिर की रक्षा भी पुलिस के जिम्मे

बल्लबगढ (म.मो.) बड़ा संकट है। पूरी दुनिया की रक्षा करने वाले अतुलित बलधामा एवं पूरा पहाड़ उठा लाने वाले हनुमान जिन्होंने बालपन में सूर्य को लड्डू समझ कर मुंह में रख लिया था, आज उनकी मंदिर की रक्षा हेतु तीन थानों की पुलिस को तैनात होना पड़ा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज ने अच्छे भले हनुमान को दलित होने का प्रमाणपत्र क्या दे दिया कि हिन्दू धर्म के ठेकेदारों में खलबली मच गयी। जो पंडे-पुजारी अब तक हनुमान को उच्च कुलीन राम-भक्त मान कर पीढी दर पीढी उसकी पूजा के सहारे अपना हलवा-मांडा खा रहे थे, उनके लिये तो यकायक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। जिस हनुमान को वे अब तक पवन सुत यानी पवन देवता का पुत्र बता कर आम लोगों को बहकाते आ रहे थे, उसे यकायक योगी महाराज ने दलित बता कर सारे मंदिरों व पूजा-पाठ को ही बेकार कर दिया। यह क्या मुसीबत खड़ी कर दी योगी जी ने बैठे बिठाये।

चलो धर्म-कर्म पवित्र-अपवित्र को तो जैसे-तैसे सह लेते, लेकिन उनका क्या करें जो हनुमान के नये दावेदार रातों-रात पैदा हो गए ? योगी जैसा प्रकांड पंडित हिन्दू धर्म के महान् ज्ञाता और ऊपर से यूपी जैसे विशाल राज्य के राजा ने जब हनुमान को दलित घोषित कर दिया तो देश भर के दलित अपने हनुमान को किसी ग़ैर-दलित की हिरासत में भला कैसे रहने दे सकते हैं। देश भर के दलित पता नहीं कब उठेंगे, उठेंगे भी या नहीं परन्तु बल्लबगढ के दलित तो उठ खड़े हुए हैं। उठें भी क्यों नहीं, धर्म की रक्षा का मामला है। धर्म की रक्षा हेतु प्राण न्योछावर करने का मार्ग तो संघी भाई सदा से ही प्रशस्त करते आये हैं तो आज दलित भाई धर्म की रक्षा से कैसे पीछे हट सकते हैं ? अपने बिछड़े दलित भगवान को पंडों की कैद से छुड़ाना उनका परम कर्त्तव्य बनता है।

हनुमान की पूजा कोई पंडा करे या दलित इससे हनुमान को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, फ़िर झगड़ा किस बात का ? झगड़ा सारा पूजा से उपजने वाली मोटी मलाई का है। हनुमान के नाम पर मंदिर में आने वाली सारी माल मलाई में से एक अंगली भर मलाई हनुमान के मुंह को लगा कर बाकी सारी मलाई को पंडे चट कर जाते हैं; बल्कि आजकल तो इस मलाई की मोटी होती परत को सम्भालने के लिये अच्छे खासे संगठन भी खड़े हो गये हैं जो अक्सर इसे कब्जाने के लिये सड़क से लेकर अदालतों तक में लड़ते हैं। ऐसे में भला फ़िर दलित क्यों पीछे रहने लगे। इस मलाई पर उनका भी तो कुछ एक बनता ही होगा।

ईएसआई अस्पतालों को आम जनता के लिये नहीं खोला जा सकता

फ़रीदाबाद (म.मो.) कुछ लोग़ों को झूठी खबरें फ़ैलाने का शौक होता है। इसी सप्ताह ऐसी ही एक खबर उड़ाई गयी कि ईएसआई अस्पताल खास कर एनएच-3 को आम जनता के लिये खोल दिया गया है। इस खबर को मजबूती देने के लिये इसे केन्द्र सरकार द्वारा घोषित भी बता दिया गया।

हकीकत यह है कि 6 दिसम्बर को ईएसआई कार्पोरेशन की बैठक हुई थी। बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में साफ़-साफ़ लिखा गया है कि ईएसआई के जिन अस्पतालों में मरीज़ कम हैं अर्थात अस्पताल की क्षमता से कम काम है वहां आम लोग़ों का भी ऑन पेमेंट इलाज किया जा सकता है। लेकिन देश भर में ईएसआई का एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें उसकी क्षमता से कम मरीज़ आते हों।

उपलब्ध भीतरी जानकारी के अनुसार ईएसआई कार्पोरेशन को यह बात कहने की नौबत इस लिये आई कि जुमलेबाज पार्टी की मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' का जो जुमला उछाला है वह पूरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हो चुका है क्योंकि सरकार के पास आम जनता को चिकित्सा सुविधा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तमाम सरकारी अस्पतालों, चाहे वे फ़ौज के हों, रेलवे के हों या किसी भी महकमे के हों, उन्हें आम आदमी के लिये खोलने का निर्देश जारी किया था। इसी कड़ी में ईएसआई के अस्पतालों को भी जोड़ा गया था। परन्तु ईएसआई समेत सभी महकमों ने इसे यह कहते हुए मानने से इन्कार कर दिया था कि उनके पास पहले से ही इतना काम है जो सम्भाले नहीं सम्भल रहा। उन्हें खुद अपने मरीज़ों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजना पड़ता है।

लेकिन ईएसआई पर जब ज़्यादा दबाव पड़ने लगा तो इसे कार्पोरेशन की मीटिंग के एजेंडे में रखा गया। विदित है कि इस मीटिंग में केन्द्रीय मज़दूर संगठनों के नेता भी शामिल होते हैं। जाहिर है जो मज़दूर एक बेहतर चिकित्सा सुविधा के नाम पर हर माह अपने वेतन का साढे 6 प्रतिशत ईएसआईसी को देता हो तो वह कैसे यह सब गुल-गपाड़ा होने देगा ?

एक मजेदार सवाल यह पैदा होता है कि सब की निगाहें एनएच-3 वाले अस्पताल पर ही क्यों हैं, उन्हें सेक्टर 8 वाला अस्पताल कयों नज़र नहीं आता जबकि 200 बिस्तर वाले उस अस्पताल में मात्र 10-12 मरीज़ ही दाखिल रहते हैं ?

कैमरा बोलता है

सैक्टर 23-24 की विभाजक सड़क पर प्लाट नं. 105 स्थित इंडियन बकट कम्पनी के सामने सड़ता गन्दगी का ढेर स्वतः बता रहा है मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान की उपलब्धियां। सैकड़ों करोड़ का टैक्स सरकार को देने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में लाखों मजदूर काम करते हैं तथा सड़क के दूसरी ओर रिहायशी क्षेत्र में भी लगभग इतने ही लोगों की बस्ती है। ये तमाम लोग इस गन्दगी के सड़ने से परेशान हैं। कई बार नगर निगम को दरखास्तें लिखने के बावजूद किसी अधिकारी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। विडम्बना यह है कि स्मार्ट सिटी प्रशासन ने जिस इको ग्रीन कम्पनी को शहर में कूड़ा निस्तारण का ठेका दे रखा है उसी की गाड़ियां (फोटो में देखें) यहां पर सारा दिन कूड़ा फैलाती रहती हैं।

5 राज्यों में मोदी - अमित की रैलियां काम न आई भाजपा ने मुंह की खाई

राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व योगी आदित्य नाथ ने जी भरकर झूठ बोला, जुमले छोड़े, साम्प्रदायिकता फैलाने का पूरा प्रयास किया, राम मंदिर का राग भी अलापा और अन्त में बुलन्दशहर में साम्प्रदायिकता का वही पुराना पन्ना भी फैंकने चले थे जो पांच साल पहले मुज्जफरनगर में फैंका था। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया।

चुनाव के परिणाम तो बेशक 11 दिसम्बर को घोषित होंगे लेकिन मोदी-अमित के माथे में पड़े बल बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत उम्मीद कहीं बची है तो वह छत्तीसगढ़ ही हो सकता है। बाकी चारों राज्यों में मतदाता ने इन्हें इनकी सही औकात बता दी है।